

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 89/18

नम्बर च
अहकाम
द्वय की जा
जासी

1. आशाराम
 2. चिरंजी
 3. तेजराम
- पुत्रान भांगला जाति मीना निवासी बडा गांव कहार (धोला भाटा) तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर।

अपी०

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाल्या जाति मीना निवासी बडा गांव कहार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भाडौती।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मलारना डूंगर।

रेस्पो०

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर मु०न० 47/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.18)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी० की और से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. रेस्पो० की और से श्री चिरंजीलाल बैरवा

निर्णय

दिनांक: 22.03.2021

3.21
प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1. अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मु०न० 47/17 निर्णय दिनांक 22.5.18 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो० ने एक वाद पत्र बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, इस आशय का पेश किया कि वादी/रेस्पो० की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में खाता संख्या नया 88 व खाता संख्या पुराना 75 के ख.नं. 4515, रकबा 0.2600 किस्म चाही-2, वाके ग्राम कहार उर्फ बडा गांव में स्थित है जिसका वादी/रेस्पो० तन्हा एकमात्र खातेदार व कब्जे काशत व्यक्ति है। उक्त आराजी वादी/रेस्पो० की पुस्तैनी आराजी है जिससे उक्त आराजी पर वादी/रेस्पो० का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है जिस पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत तरीके से अपने लट्ट के बल पर व राजनैतिक पहुंच होने के कारण नाजायज रूप से उक्त आराजी पर आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है तथा इसी कब्जे की आड लेकर प्रतिवादीगण/अपी० द्वारा उक्त आराजी के आधे हिस्से में से लगभग 05-05 फिट गहरी खाई करवाकर मिट्टी बेच दी है। वादी/रेस्पो० उक्त आराजी का आधा हिस्सा प्रतिवादीगण/अपीलांट के कब्जे में होने से अब तक अनभिज्ञ था। वादी/रेस्पो० द्वारा दिनांक 13.06.2017 को उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसील हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 08.11.2017 को आदेश कंमा/एल.आर./2017/2615 दिनांक 13.06.2017 की अनुपालना में कहार उर्फ बडा गांव कहार के आराजी ख.नं. 4470, 4471, 4472, 4501, 4502, 4503, 4515 व 4519 का मौके पर पटवारी हल्का द्वारा पुलिस जाप्ते के साथ सीमाज्ञान किया गया जिसमें ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है० के हिस्सा 1/2 पर कब्जा प्रतिवादीगण/अपी० का बताया गया। प्रतिवादीगण/अपी० के कब्जे में उक्त आराजी स्पष्ट रूप से कब्जे में होना पाया गया तो वादी/रेस्पो० ने प्रतिवादीगण/अपी० से कहा कि उक्त आराजी मुझे संभलाओं तो प्रतिवादीगण/अपी० साफ मुकर गये और कहा कि ये जमीन हम

तुम्हें कभी नहीं देंगे तथा इसे हम अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवायेंगे, तब जाकर वादी/रेस्पो0 द्वारा दिनांक 15.11.2017 को जमाबंदी की नकल लेकर व दिनांक 10.11.2017 को मौका रिपोर्ट की नकल लेकर उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। पूर्व में भी जमीन के डोल को लेकर वादी/रेस्पो0 व प्रतिवादीगण/अपी0 के बीच विवाद हुआ था जिसमें पंचों द्वारा दिनांक 24.12.2007 को यह तय किया गया था कि राभी अपनी-अपनी जमीन का सीमाज्ञान करवायेंगे तथा जिसके हिस्से में जिसकी जमीन निकलेगी वह उसी राजी खुशी उसके हक में छोड़ देगा परन्तु प्रतिवादीगण/अपी0 ने उक्त पंचनामों का आज तक कोई पालन नहीं किया। वादी/रेस्पो0 को उक्त आराजी खाता संख्या 88 में ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है0 किस्म चाही-2 के आधे हिस्से पर से प्रतिवादीगण/अपी0 को बेदखल करवाने का कानूनन अधिकार है जिसे बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा वादी/रेस्पो0 की उक्त खातेदारी की आराजी के आधे हिस्से में से उठाई गई मिट्टी का मुआवजा प्रतिवादीगण/अपी0 से दिलवाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत ने अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 ने अपीलांत के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया था एवं पत्रावली दिनांक 21.05.2018 को जवाब दावा हेतु नियत थी एवं प्रकरण को अटल सेवा केन्द्र भाडौती में दिनांक 22.05.2018 को नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के बयान लिये बिना ही आर्डरशीट पर ही निर्णय कर दिया। जबकि अपीलांत उपस्थित भी नहीं थे। अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही एक पक्षीय रूप से पारित किया है। विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 4551 रकबा 0.26 है0 पर अपीलांतगण का कदीमी समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। इसी उद्देश्य से रेस्पो0 ने अपीलांतगण को बेदखल किये जाने की इस्तदुआ की थी। अधिनस्थ न्यायालय आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल भूत सिद्धान्तों के विपरीत व इल्लीगल, इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 12.07.2018 को होने से अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 25.05.18 अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में खाता संख्या नया 88 व खाता संख्या पुराना 75 के ख.नं. 4515, रकबा 0.2600 किस्म चाही-2, वाके ग्राम कहार उर्फ बडा गांव में स्थित है जिसका रेस्पो0 तन्हा एकमात्र खातेदार व कब्जे काश्त व्यक्ति है। उक्त आराजी रेस्पो0 की पुस्तैनी आराजी है जिससे उक्त आराजी पर रेस्पो0 का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है जिस पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत तरीके से अपने लट्ठ के बल पर व राजनैतिक पहुंच होने के कारण नाजायज रूप से उक्त आराजी पर आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है तथा इसी कब्जे की आड लेकर अपी0 द्वारा उक्त आराजी के आधे हिस्से में से लगभग 05-05 फिट गहरी खाई करवाकर मिट्टी बेच दी है। रेस्पो0 उक्त आराजी का आधा हिस्सा अपीलांत के कब्जे में होने से अब तक अनभिज्ञ था। रेस्पो0 द्वारा

दिनांक 13.06.2017 को उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसील हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार गलारना झूंगर द्वारा दिनांक 08.11.2017 को आदेश क्रमा/एल.आर/2017/2615 दिनांक 13.06.2017 की अनुपालना में कहार उर्फ बडा गांव कहार के आराजी ख.नं. 4470, 4471, 4472, 4501, 4502, 4503, 4515 व 4519 का मौके पर पटवारी हल्का द्वारा पुलिस जापते के साथ सीमाज्ञान किया गया जिसमें ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है० के हिस्सा 1/2 पर कब्जा अपी० का बताया गया। अपी० के कब्जे में उक्त आराजी स्पष्ट रूप से कब्जे में होना पाया गया तो रेस्प० ने अपी० से कहा कि उक्त आराजी मुझे संभलाओं तो अपी० साफ मुकर गये और कहा कि ये जमीन हम तुम्हें कभी नहीं देंगे तथा इसे हम अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवायेंगे, तब जाकर रेस्प० द्वारा दिनांक 15.11.2017 को जमाबंदी की नकल लेकर व दिनांक 10.11.2017 को मौका रिपोर्ट की नकल लेकर उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। पूर्व में भी जमीन के डोले को लेकर रेस्प० व अपी० के बीच विवाद हुआ था जिसमें पंचो द्वारा दिनांक 24.12.2007 को यह तय किया गया था कि सभी अपनी-अपनी जमीन का सीमाज्ञान करवायेंगे तथा जिसके हिस्से में जिसकी जमीन निकलेगी, वह उसे राजी खुशी उसके हक में छोड़ देगा परन्तु अपी० ने उक्त पंचनामें का आज तक कोई पालन नहीं किया। रेस्प० को उक्त आराजी खाता संख्या 88 में ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है० किस्म चाही-2 के आधे हिस्से पर से अपी० को बेदखल करवाने का कानूनन अधिकार है जिसे बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अपी० द्वारा रेस्प० की उक्त खातेदारी की आराजी के आधे हिस्से में से उठाई गई मिट्टी का मुआवजा अपी० से दिलवाया जावे। अपीलार्थी का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपील 27.08.2018 को पेश की है। यह मियाद बहार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक अपीलार्थीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

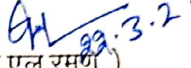
6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. प्रकरण के परीक्षण से तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 88 वाके ग्राम कहार उर्फ बडा गांव के अनुसार ख.नं. 4515 रकबा 0.26 है० जगदीश पुत्र बाल्या मीना सा.देह के नाम दर्ज है। मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.2017 के अनुसार मौके पर ख.नं. 4515 रकबा 0.26 है० में से 0.13 है० जगदीश पुत्र बाल्या का कब्जा नहीं है। मौके पर कोई फसल नहीं है। विचारण न्यायालय ने वाद दिनांक 23.11.2017 को दायर किया गया है। दिनांक 19.12.2017 को जवाब प्रतिवादीगण में पत्रावली नियत कर दी गयी। दिनांक 22.05.2018 तक कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 22.

2018 की आर्डर शीट में अभिलिखित है कि "वकील फरीकन उपस्थित। प्रकरण में 16.01.2018 से अब तक कई अवसर देने के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं किया है तथा जान बूझकर दावे के निर्णय में विलम्ब किया जा रहा है। वकील वादी ने जवाब दावा बंद करते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया है।" अपी०/प्रति० लम्बी अवधि के पश्चात् भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड में रेसपो० खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसकी आधी भूमि पर अपी० का अतिक्रमण है। इसलिए रेसपो० आराजी से अतिक्रमण हटवाने का अधिकारी है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर का मु०नं० 47/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(वी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर